

निगम जलकर वसूली निजी एजेंसियों को सौंपने पर सियासत कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी, महापौर ने किया पलटवार

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम द्वारा जलकर (वाटर टैक्स) वसूली का जिम्मा निजी एजेंसियों को सौंपने की तैयारी पर राजनीतिक घमासान मच गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे तानाशाही बना फैसला बताते हुए जोरदार विरोध किया है और व्यवस्था नहीं बदलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं, दूसरी ओर महापौर मालती राय ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे रहवासी समितियों की मांग पर लिया गया व्यावहारिक निर्णय बताया है।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निगम अब घर-घर निजी एजेंट भेजकर जलकर की वसूली कराने की तैयारी कर रहा है। जो लोग समय पर कर जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनके घरों तक निजी एजेंसियों के एजेंट पहुंचेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रेम इन कार्डसिल में इस तरह का प्रस्ताव आखिर कैसे पास कर दिया गया। कांग्रेस का साफ कहना

सुबह ६ से शाम ७ बजे तक डाउन रहता है सर्वर

भोपाल, (एजेंसी)। स्वािमित्व योजना के तहत जमीनों और मकानों की रजिस्ट्री का काम तकनीकी दिक्कतों की वजह से बाधाओं का सामना कर रहा है। पोर्टल के धीमा चलने और सर्वर डाउन रहने के कारण रजिस्ट्रियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है, जिससे प्रशासन द्वारा तय किए गए बड़े लक्ष्यों को पूरा करना पटवारियों के लिए खड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हालात यह हैं कि दिनभर मशगलकत के बाद भी एक पिनभरी महज ५ से ७ मकानों की ही रजिस्ट्री कर पा रहा है। प्रशासन की ओर से इस योजना के तहत रोजना १००० से ज्यादा रजिस्ट्रियां करने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। स्थिति यह है कि सुबह ६ बजे से लेकर शाम ७ बजे तक सर्वर लगातार डाउन रहता है या पोर्टल बेहद धीमा चलता है। इस वजह से घंटों

खड़ी बस को टूक ने मारी टक्कर ८ यात्री घायल

राजगढ़, (एजेंसी)। जिले के सारंगपुर नेशनल हाईवे पर रविवार सुबह करीब ६ बजे यात्रियों से भरी खड़ी बस को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में आठ यात्री घायल हो गए। इनमें पांच को गंभीर चोट आई है। एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद शाजापुर रेफर किया गया। जानकारी अनुसार कमला बस (यूपी ७८ सी) इंदौर से अशोकनगर जा रही थी। बस में करीब ४० यात्री सवार थे।

जेन-जी तक पहुंच बढ़ाने की संघ की रणनीति

भोपाल, (एजेंसी)। युवाओं के बदलते विचार, सोशल मीडिया पर उनकी बढ़ती सक्रियता और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर मुखर होती भागीदारी के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने नई पीढ़ी से संवाद बढ़ाने की दिशा में कदम तेज किए हैं। मालवा के बाद अब संघ का फोकस महाकौशल पर है। संच प्रमुख डॉ॰ मोहन भागवत २४ से २६ अक्टूबर तक जबलपुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान २५ अक्टूबर को कालेंजों में पढ़ते युवा स्वयंसेवकों के शिविर में उनके संवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

संघ की इस पहल को केवल संगठनात्मक गतिविधि के तौर पर नहीं, बल्कि नई पीढ़ी की सोच, आकांक्षाओं और सामाजिक सरोकारों को समझने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। डिजिटल माध्यमों से जुड़ी जेन-जी पारंपरिक संवाद के तरीकों से अलग अपनी राय रखती है। ऐसे में संघ युवाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के साथ उन्हें राइ, समाज और संगठन से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श के लिए जोड़ना चाहता है।

जनगणना २०२७ का दूसरा चरण तय समयसे पहले संभव

४० सवालों के साथ घर-घर होगा सर्वे; सैन्य क्षेत्रों का डाटा रहेगा गोपनीय

भोपाल, (एजेंसी)। अगले साल फरवरी माह से शुरू होने वाली जनगणना का दूसरा चरण तय समय से पहले भी शुरू हो सकता है। बड़े ब्लॉक में लोगों की संख्या अधिक होने के कारण इन्हें छोटे ब्लॉक में बांटा जाना है और लोगों की गणना में ४० सवालों के साथ अधिक समय लग सकता है इसलिए एका संभव है। इसको लेकर उच्च स्तर पर मंथन किया जा रहा है। वहीं स्पेशल एरिया जैसे छावनी क्षेत्र की आबादी, एयरफोर्स व अन्य सैन्य बलों की जानकारी पहले ही गोपनीय स्तर पर भेज दी जाएगी। इसको लेकर क्षेत्रों की सूची तैयार कर दी गई है। बता दें कि जनगणना-२०२७ के द्वितीय चरण का कार्य फरवरी माह से प्रारंभ होगा। द्वितीय चरण में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण के माध्यम से जनगणना का कार्य किया जाएगा। नगरीय निकाय से जुड़े अधिकारियों को जनगणना के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। द्वितीय चरण में घर-घर जाकर

है कि जलकर वसूली का काम पूरी तरह से निगम को खुद करना चाहिए, न कि किसी निजी एजेंसी को। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि इस व्यवस्था को तुरंत नहीं बदला गया, तो कांग्रेस आंदोलन करेगी।

महापौर मालती राय का पलटवार कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए महापौर मालती राय ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बिना किसी विषय का ठीक से अध्ययन किए बयानबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नई व्यवस्था शहर की हर कॉलोनी में लागू नहीं होगी, बल्कि यह केवल उन्हीं कॉलोनियों के लिए है जहां बक्क कनेक्शन हैं। महापौर ने बताया कि विभिन्न रहवासी समितियों की लगातार मांग आ रही थी कि बक्क कनेक्शन वाले इलाकों में जलकर की वसूली और प्रबंधन में भारी दिक्कतें आ रही हैं। यह व्यवस्था पूरी तरह से स्वीच्छिक है। संबंधित रहवासी समितियों को सहमति मिलने पर ही निजी एजेंसी इस पर काम करेगी। यदि कोई समिति या क्षेत्र इसके लिए मना कर देता है,

तक डाउन रहता है सर्वर नहीं बंद पा रहा है और तय टारगेट तक पहुंचना असंभव सा नजर आ रहा है। **पहले भी हो चुका है योजना का विरोध** गौरतलब है कि इस योजना को लेकर पहले भी येवनी स्तर पर विरोध के सुरू उठ चुके हैं। शुरुआत में पटवारियों ने इस पूरी प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद शासन-प्रशासन स्तर से मिले आश्वासन के बाद उन्होंने देवावरा काम शुरू किया था। उन एक बार फिर तकनीकी खामियों और सुस्त सर्वर के कारण काम में आ रही रूकावटों से प्रशासनिक अमले और मैदानी कर्मचारियों के बीच मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

रिश्ते के देवर ने हड़प लिये ५० लाख के गहने

पति को झूठे मामले में फंसाने की आरोपित दे रहा धमकी

जबलपुर, (एजेंसी)। गोरखपुर थाना क्षेत्र में रिश्ते के देवर पर विश्वास कर करीब ५० लाख रुपये के सोने और हीरे के आभूषण देने वाली महिला ने गहने वापस नहीं मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि युवक ने आभूषण मणपुरम फाइनंसे लिमिटेड की कंपनी शाखा में गिरवी रखकर कर्ज लिया और गहने वापस मांगने पर महिला के पति को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा ३१६(२)

बोएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, संजीवनी नगर निवासी ३७ वर्षीय प्रियंका हिमोले ने १७ अक्टूबर २०२६ को गोरखपुर थाने में लिखित शिकायत दी। उन्होंने बताया कि कालीमठ, मदनमहल निवासी शिवम हिमोले उनका रिश्ते का देवर है और उनके पति नितिन हिमोले के कार्यालय में काम करता था। पारिवारिक संबंध होने के कारण परिवार शिवम पर विश्वास करता था। वह समय-समय पर उनके पति से

पिछले महीने डॉ. भागवत ने इंदौर और उज्जैन का तीन दिवसीय दौरा किया था। उज्जैन में आयोजित धर्मसभा में मालवा के स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों की भी शामिल किया गया था। इस दौरान युवाओं के साथ, सिधे संवाद का अवसर मिला। अब इसी क्रम में महाकौशल के युवाओं के साथ चर्चा की तैयारी है। महाकौशल प्रांत के प्रचार प्रमुख विनोद कुमार के अनुसार, २५ अक्टूबर को संघ प्रमुख प्रांत के युवा स्वयंसेवकों के शिविर में शामिल होंगे। शिविर में कालेंजों में पढ़ते वाले स्वयंसेवकों से बातचीत और उनका संबोधन प्रस्तावित है। हालांकि, संवाद के विषयों की विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। **राष्ट्रवाद से आगे युवाओं के सवालों पर भी नजर** संघ के इस कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, सामाजिक समन्वय और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही युवाओं की बदलती प्राथमिकताओं और समाज को लेकर उनके नजरिये को समझना भी इस संवाद का अहम पहलू हो सकता है। आज की जेन-जी रोजगार, शिक्षा, अवसरों, सामाजिक पहचान और सार्वजनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर डिजिटल मंचों के जरिए अपनी बात रखती है। ऐसे में युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए केवल विचार रखने के बजाय उनकी बात सुनना भी महत्वपूर्ण हो गया है। संघ का यह संवाद इस कसौटी पर भी देखा जाएगा कि नई पीढ़ी के सवालों और अपेक्षाओं को कितनी जगह मिलती है।

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में चयन के लिए एक अंकसूचियों के इस्तेमाल का ऐसा खेल सामने आया है, जिसमें असली परीक्षा में असफल अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के कथित बोर्डों की मार्कशीट पर ९० से ९५ प्रतिशत तक अंक हासिल कर नौकरी पाने में सफल हो गए। ग्यालियर-चंबल अंचल के दत्तिया और शिवपुरी में सामने आए दो मामलों ने भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजों के सत्यापन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों मामलों में जिन बोर्डों की अंकसूचियों के आधार पर नियुक्तियां हुईं, जांच में उनका अस्तित्व ही संदिग्ध पाया गया।

दत्तिया में उत्तर प्रदेश के महर्षि वाल्मीकि संस्कृत एवं योग शिक्षा संस्थान की अंकसूचियों से नियुक्तियां हासिल करने का मामला सामने आया, जबकि शिवपुरी में राजस्थान के कथित मुक्त विद्यालय शिक्षा परिषद, सूरतगढ़ की मार्कशीट के आधार पर आंगनबाड़ी सहायिका की नौकरी पाने का खुलासा हुआ। दोनों मामलों में फर्जी वेबसाइट, संदिग्ध पते और अंकसूचियों की विश्वसनीयता को लेकर एक जैसा पैटर्न सामने आया है। कार्रवाई के नाम पर अब तक नियुक्तियां निरस्त करने और संबंधित महिलाओं को नौकरी से हटाने तक कदम उठाए गए हैं। लेकिन कथित

तो वहाँ यह व्यवस्था बिल्कुल लागू नहीं की जाएगी।

घर घर नर्मदा का जल पहुंचाया भाजपा नेता डॉ हितेश बाजपेयी ने कहा- करोड़ रुपए लगाकर सरकार ने घर घर नर्मदा का जल पहुंचाया है। भोपाल के हर वार्ड में नर्मदा का जल पहुंच रहा है। पानी की भी दर होता है जल की दरों का संग्रह करना नगर निगम का काम है। कांग्रेस को दिक्कत है तो आपति दर्ज करना चाहिए। जलकरका संग्रह कौन कर रहा है इससे कांग्रेस को कोई आपति नहीं होना चाहिए। केवल व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने से अराजकता पैदा होती है।

ओबीसी आरक्षण पर भाजपा ने बढ़ाई सक्रियता, कांग्रेस में रणनीति पर मंथन

भाजपा विधायक सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में, कांग्रेस समिति के भरोसे

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में २७ प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा और कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ आरक्षण को कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि पिछड़ा वर्ग के बीच अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता बनाए रखने की भी है। भाजपा ने अपने विधायकों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने की तैयारी की है, जबकि कांग्रेस अभी आंदोलन की दिशा और नेतृत्व को लेकर विचार-विमर्श कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आरक्षण की लड़ाई में कौन-सा दल राजनीतिक पहल करता है और कौन प्रतिक्रिया देने तक सीमित रहता है।

प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। इसके समानांतर भाजपा विधायकों के माध्यम से भी कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाने की रणनीति बना रही है। पार्टी के लिए यह मुद्दा पिछड़ा वर्ग के बीच अपनी प्रतिबद्धता

रीवा सम्भाग

पत्नी को बचाने दौड़ा पति दोनों की कंठ से मौत

छतरपुर, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के मातुवाय थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में शनिवार को दर्दनाक हादसे में पति-पत्नी की कंठ लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, २४ वर्षीय रुकमन खेत से मवेशियों के लिए चारा लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रहा हाईटेशन बिजली का तार टूटकर उस पर गिर गया। कंठ की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गईं।

पत्नी को कंठ में फंसा देखकर २८ वर्षीय पति चंद्रभान प्रजापति उसे बचाने दौड़ा, लेकिन वह भी कंठ की चपेट में आ गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे ने बिजली विभाग की लापरवाही और खुले तारों से होने वाले खतरों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आंबेसी आरक्षण पर भाजपा ने बढ़ाई सक्रियता, कांग्रेस में रणनीति पर मंथन

दिखाने का अवसर है। आरक्षण पर बढ़ते विरोध और सामाजिक संगठनों की सक्रियता के बीच भाजपा नहीं चाहती कि इस मुद्दे पर विषय उसे घेरने का मौका पाए। हालांकि, कानूनी लड़ाई में याचिका दायित्व कायें और आरक्षण को अंतिम रूप से लागू करना पाने दो अलग-अलग चरण हैं। इसका फैसला न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक प्रवाधानों के आधार पर ही होगा।

कांग्रेस के सामने श्रेय और रणनीति का सवाल २७ प्रतिशत आरक्षण का फैसला कमल नाथ सरकार का कार्यकाल में २०१९ में हुआ था। तब सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण १४ से बढ़ाकर २७ प्रतिशत किया गया था। लिलाका कांग्रेस के पास इस मुद्दे पर अपनी सरकार के फैसले को राजनीतिक आधार बनाने का अवसर है। लेकिन उनका पार्टी के सामने सवाल है कि वह कानूनी लड़ाई खुद लड़े, सामाजिक संगठनों को आगे रखे या अपने ओबीसी नेताओं के नेतृत्व में

आर्थिक सहायता भी लेता था।

शिकायत के मुताबिक, ८ सितंबर २०२३ को शिवम रुपये की जरूरत बताकर उनके घर पहुंचा। उसने आर्थिक परेशानी का हवाला देते हुए गहने देने की मांग की और छह से सात महीने में वापस करने का भरोसा दिलाया। उसकी बात पर विश्वास कर प्रियंका और उनके पति ने उसे करीब ३० तोला वजन के सोने और हीरे के आभूषण दे दिए। इनमें डायमंड ईयर रिंग, सोने का हार, कड़े, चेन, डायमंड रिंग, सोने की अंगुठियां और ब्रेसलेट शामिल थे। महिला ने इनकी कीमत करीब ५० लाख रुपये बताई है। गहने देते समय उन्होंने मोबाइल से उनकी तस्वीरें भी लीं थीं।

महिला का आरोप है कि शिवम ने इन आभूषणों को मणपुरम फाइनंसे लिमिटेड की कंपनी शाखा में गिरवी रखकर कर्ज लिया। तय समय बीतने के बाद वह उन्होंने गहने वापस मागे, तो वह टालमटोल करता रहा। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि वह उन्हीं आभूषणों को गिरवी रखकर आगे भी कर्ज लेता रहा। प्रियंका के अनुसार, करीब तीन महीने पहले देवावरा गहने मांगने पर शिवम ने उन्हें लौटाने से इन्कार कर दिया। साथ ही, उनके पति नितिन हिमोले को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर शिवम हिमोले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा ३१६(२) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। मामले में आरोपों की जांच की जा रही है।

फर्जी बोर्ड की ९५ प्रतिशत मार्कशीट से सरकारी नौकरी

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में चयन के लिए एक अंकसूचियों के इस्तेमाल का ऐसा खेल सामने आया है, जिसमें असली परीक्षा में असफल अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के कथित बोर्डों की मार्कशीट पर ९० से ९५ प्रतिशत तक अंक हासिल कर नौकरी पाने में सफल हो गए। ग्यालियर-चंबल अंचल के दत्तिया और शिवपुरी में सामने आए दो मामलों ने भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजों के सत्यापन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों मामलों में जिन बोर्डों की अंकसूचियों के आधार पर नियुक्तियां हुईं, जांच में उनका अस्तित्व ही संदिग्ध पाया गया।

दत्तिया में उत्तर प्रदेश के महर्षि वाल्मीकि संस्कृत एवं योग शिक्षा संस्थान की अंकसूचियों से नियुक्तियां हासिल करने का मामला सामने आया, जबकि शिवपुरी में राजस्थान के कथित मुक्त विद्यालय शिक्षा परिषद, सूरतगढ़ की मार्कशीट के आधार पर आंगनबाड़ी सहायिका की नौकरी पाने का खुलासा हुआ। दोनों मामलों में फर्जी वेबसाइट, संदिग्ध पते और अंकसूचियों की विश्वसनीयता को लेकर एक जैसा पैटर्न सामने आया है। कार्रवाई के नाम पर अब तक नियुक्तियां निरस्त करने और संबंधित महिलाओं को नौकरी से हटाने तक कदम उठाए गए हैं। लेकिन कथित

एमपी बोर्ड में फेल, दूसरी मार्कशीट में ९५ प्रतिशत अंक शिवपुरी जिले के पोहरी क्षेत्र के अमरगढ़ में संजना यादव का आंगनबाड़ी सहायिका पद पर चयन हुआ था। नियुक्ति के लिए प्रस्तुत १२वीं की अंकसूची राजस्थान के मुक्त विद्यालय शिक्षा परिषद, सूरतगढ़ के नाम से जारी बताई गई थी। इसमें ९५ प्रतिशत अंक दर्शाए गए थे। जांच में सामने आया कि संबंधित अभ्यर्थी ससई मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की नियमित परीक्षा में फेल हुई थी। इसी तरह शिवपुरी में रचना धाण्ड की ९०.८ प्रतिशत अंक वाली अंकसूची पर संदेह होने के बाद सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई। राजस्थान के शिक्षा विभाग की

माताके जयकारोंसे गूंजा मंडला, अष्टमीपर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

मंडला, (एजेंसी)। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर मंडला शहर में अष्टमी का त्योहार पूरे उत्साह, श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। नवरात्रि के दौरान पूरा शहर माता रानी की भक्ति में सरगोबर नजर आ रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित माता भगवती की भव्य प्रतिमाओं और आकर्षक पंडालों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का मिलसिला जारी है। वहां, शाम होते ही माता के जयकारोंसे शहरका वातावरण भक्तिमय हो उठता है। प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की चहल-पहल बढ़ने से नवरात्रिकी रौनक देखते ही बन रही है।

अष्टमी पर माता के दरबार में उमड़ी भीड़ नवरात्रि के आठवें दिन अष्टमी पर माता रानी के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने की मिला। भक्तों ने माता के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। शहर के विभिन्न

आंदोलन खड़ा करे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की अध्यक्षता में समिति बनाई है। समिति के जरिए विचार-विमर्श कर आगे की रणनीति तय करने की बात कही गई है। फिलहाल कांग्रेस की सक्रियता घंटकों और बयानों से आगे किस रूप में बढ़ेगी, यह स्पष्ट नहीं है।

सामाजिक संगठनों ने बढ़ाया दबाव ओबीसी महापक्षा सहित विभिन्न संगठन आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। भोपाल में छात्रवृत्ति और आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। दूसरी ओर, अलग-अलग स्थानों पर आरक्षण के सवर्धन में नेताओं और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी सामने आया है। इससे स्पष्ट है कि यह मुद्दा अब केवल अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दबाव का रूप ले रहा है।

आनलाइन ठगी के तीन मामले दर्ज

ड्रायफूट का आईर देने के बाद करीब १.७७ लाख रुपये की ठगी

जबलपुर, (एजेंसी)। शहर में सायबर ठगी के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसी क्रम में तीन और नये मामले प्रकाश में आए हैं। महालावा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से ड्रायफूट मंगाना एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को महंगा पड़ गया। स्टार सिटी निवासी ६५ वर्षीय आर. के. गुप्ता ने फैसलपुर वीरधाम ड्रायफूड का लिंक देखकर सामान आईर किया था। विवेकता ने एक हजार रुपये एडवांस भरो, जिसे उन्होंने १० अक्टूबर को पेटीएम के माध्यम से अपने स्टेट बैंक खाते से ट्रान्सफर कर दिया।सामग्री नहीं मिलने पर उन्होंने विक्रेता से संपर्क किया। आरोप है कि विक्रेता ने व्हाट्सएप के माध्यम से पेटीएम खोलने को कहा और बातचीत के दौरान उन्हें गुमराह कर १५ अक्टूबर को अलग-अलग रकम ट्रान्सफर करा ली। शिकायत में कुल करीब १.७७ लाख रुपये की धोखाधड़ी की बात कही गई है।पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा ३१८(४) और ३१९(२) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

महिला से ३५.८०० रुपये की धोखाधड़ी

बरेला थाना क्षेत्र में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्राम खरपरिया नीमखेड़ा निवासी निषा चौधरी ने १६ अक्टूबर को को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गलत पहचान

शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर सजे माता रानी के भव्य दरबार, देर शाम तक दर्शन के लिए पहुंचते रहे भक्त

स्थानों पर स्थापित माता की प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए देर शाम तक लोगों का पहुंचना जारी रहा। आकर्षक विद्युत सजावट, सुसज्जित पंडाल और धार्मिक वातावरण ने पर्व की भव्यता को और बढ़ा दिया।

बड़ी खेरी में भव्य पंडाल, प्रदर्शनों भी आकर्षण

शहर के डिंडोरी मार्ग स्थित बड़ी खेरी क्षेत्र में बड़ी खेरी दुर्गास्त्व समिति द्वारा प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी माता रानी का भव्य दरबार सजाया गया है। समिति की ओर से आकर्षक पंडाल तैयार कर आम नागरिकों के लिए माता के दर्शन की व्यवस्था की गई है। पंडाल की सजावट और माता की प्रतिमा के

एमपी की अदालतों में २१.४२ लाख मुकदमे लंबित

न्यायिक ढांचे, रिक्त पदों और प्रकरण प्रबंधनकी चुनौतियोंसे बढ़ रहा मुकदमोंका बोझ

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश की जिला और अप्रीनस्थ अदालतों में मुकदमों का लंबित बोझ न्यायिक व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। लोकसभा में प्रस्तुत केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, ३० जुलाई २०२६ तक प्रदेश की जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में कुल २१,४२,२८० मामले लंबित थे। इनमें ३,४८,६७० मामले पांच साल से अधिक और ३६,०८० मामले दस साल से ज्यादा समय से फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये आंकड़े केवल लंबित मुकदमों की संख्या नहीं बताते, बल्कि उन लोगों की परेशानी भी सामने लाते हैं, जो संपत्ति विवाद, उत्तराधिकार, सेवा संबंधी मामलों और आपराधिक प्रकरणों में न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुकदमों के लंबे समय तक लंबित रहने से संबंधित पक्षों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश की अदालतों में लंबित मामलों के आंकड़े बताते हैं कि पुराने मुकदमों का निपटारा न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। पांच साल से अधिक पुराने ३.४८ लाख

से ज्यादा मामलों में बड़ी संख्या ऐसे प्रकरणों की है, जिनमें पक्षकार लंबे समय से अंतिम फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं, दस साल से अधिक समय से लंबित ३६,०८० मामले त्वरित न्याय की जरूरत को रेखांकित करते हैं। हालांकि, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं होता कि कितने मामलों में देरी का कारण न्यायाधीशों की कमी, अधोसंरचना, गवाहों की अशुपलब्धता, बार-बार स्थान या अन्य प्रक्रियागत कारण हैं। इसके लिए एमालों की श्रेणीवार और जिला-वार समीक्षा आवश्यक है।

न्यायिक अधोसंरचना और रिक्त पद भी अहम लंबित मामलों की चुनौती केवल सुनवाई तक सीमित नहीं है। पर्याप्त न्यायालय कक्ष, न्यायिक अधिकारी, कर्तव्यचारी और अन्य संसाधन भी समय पर न्याय उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगस्त २०२६ में अनुपूरु जिला न्यायालय के भवन से संबंधित मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायिक अधोसंरचना की लंबित परीयोजनाओं और वित्तीय संजरी में देरी का मुद्दा उठा था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि संबंधित मूल्यांकन समिति ने १७ जुलाई २०२६ को हुई बैठक में ४५ करोड़ रुपये की मंजूरी को अनुशंसा की थी, लेकिन नितीय कारणों से

आवंटन में विलंब हुआ। यह स्थिति बताती है कि न्यायिक व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने के लिए भवनों और सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना भी जरूरी है। **डिजिटल व्यवस्था से मिलेगी मदद, लेकिन पर्याप्त नहीं** केंद्र सरकार की ई-कोर्ट्स परियोजना के तीसरे चरण (२०२३-२०२७) के लिए ७,२१० करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके तहत डिजिटल कामकाज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और न्यायिक अभिलेखों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल सुविधाओं से सुनवाई और अभिलेखों के प्रबंधन में मदद मिल सकती है, लेकिन लंबित मुकदमों का प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त न्यायिक अधिकारी, कर्तव्यचारी, न्यायालय कक्ष और बेहतर प्रकरण प्रबंधन भी आवश्यक हैं। ऐसे में पुराने मुकदमों की नियमित समीक्षा, जिला-वार लंबित मामलों का सार्वजनिक विवरण, रिक्त पदों की भरने और न्यायिक अधोसंरचना की परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर देना होगा। न्याय मिलने में लगने वाला समय कम करना पूरी न्यायिक व्यवस्था के साथ सरकार और प्रशासनकी भी साझा जिम्मेदारी है।

आदिवासी छात्रों से गाली-गलौज का मामला गरमाया !

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आदिवासी छात्रों को कथित तौर पर गाली देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना से नाराज आदिवासी समाज और संगठन जयस ने अंबेडकर पार्क में भारी संख्या में पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि आरोपी निर्लंबित टीआईए रतन सिंह परिहार के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले आदिवासी बच्चों ने अपनी कुछ

मेडिकल कालेजके वाई से मरीजके परिजनको पर्स गायब जबलपुर, (एजेंसी)। गढ़ा थाना क्षेत्र में मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती महिला के सामान और नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है। सिंगरीली जिले के बेदुन निवासी दीपक गुप्ता (३०) ने पुलिस को बताया कि उन्होंने १४ अक्टूबर को अपनी मां रीता गुप्ता को किडनी के इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया था।१६ अक्टूबर की रात करीब ८ से ९ बजे के बीच इलाज के लिए उनका लेने के लिए एक जोड़ी कनबूढ़ी, मंगलसूत्र और चांदी की पायल उतरवाकर रखी गई थी। पर्स में ६,२०० रुपये नकद भी थे। इसी दौरान उनकी मां बाबुरूम गईं। वापस आने पर पर्स गायब मिला।दीपक ने अपनी मां के पास भर्ती मदनमहल निवासी चंदा बाई पर संदेह बताया है।

आदिवासी छात्रों से गाली-गलौज का मामला गरमाया !

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आदिवासी छात्रों को कथित तौर पर गाली देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना से नाराज आदिवासी समाज और संगठन जयस ने अंबेडकर पार्क में भारी संख्या में पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि आरोपी निर्लंबित टीआईए रतन सिंह परिहार के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले आदिवासी बच्चों ने अपनी कुछ

मेडिकल कालेजके वाई से मरीजके परिजनको पर्स गायब जबलपुर, (एजेंसी)। गढ़ा थाना क्षेत्र में मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती महिला के सामान और नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है। सिंगरीली जिले के बेदुन निवासी दीपक गुप्ता (३०) ने पुलिस को बताया कि उन्होंने १४ अक्टूबर को अपनी मां रीता गुप्ता को किडनी के इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया था।१६ अक्टूबर की रात करीब ८ से ९ बजे के बीच इलाज के लिए उनका लेने के लिए एक जोड़ी कनबूढ़ी, मंगलसूत्र और चांदी की पायल उतरवाकर रखी गई थी। पर्स में ६,२०० रुपये नकद भी थे। इसी दौरान उनकी मां बाबुरूम गईं। वापस आने पर पर्स गायब मिला।दीपक ने अपनी मां के पास भर्ती मदनमहल निवासी चंदा बाई पर संदेह बताया है।

विधवा प्रेमिका की घेरकर हत्या, १० साल से अधिक समय से थे, प्रेम संबंध

जागर, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के जावरा के पिपलोटोडा क्षेत्र में अंतर